an>

Title: Regarding situation arising out of verdict of Supreme Court to conduct National Eligibility Entrance Test for medical courses in the country especially the medium of Examination.

–

माननीय अध्यक्षः डॉ. काकोली घोÂष दस्तीदार।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं उनका नाम ले रही हूं। काकोली घोÂष उन्हीं का नाम है न। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

â€¦(व्यवधान)

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Hon. Madam, I wish to draw your attention and the attention of this august House to a very serious condition in which the future of lakhs of students of this country is going to get jeopardized by an order. We have nothing against the order. But this should be done in phases. It cannot be just done today when the Joint Entrance Exam is supposed to be held on the 17th in West Bengal. Maintaining a lot of transparency, a West Bengal Joint Board was formed for entrance into medical professionals and other branches. The students have been preparing in remote areas in their vernacular language for 2-3 years ahead for this exam. But suddenly they are faced with this situation when they have to sit for a common test in which there is around 30 per cent difference between the syllabuses of Central Board and State's Board. How can we ask these students from remote areas to appear for this exam, which takes about two-three years to prepare, within such a short span of time. I have myself prepared for the exam quite long back.

The West Bengal Government has formed a board wherein transparency has been maintained. We have kept a provision for a separate list for backward students coming from SC, ST, OBC, Category-A and Category-B. We are trying to revive the medical delivery system in our country. All the hon. Members present here would agree that the medical delivery system needs to be upheld. The World Health Organisation report shows that there is a lack of doctors in our country. The students from remote areas are coming up and studying on their own to appear for this exam. Even if it has be done and if you are angry with certain person or certain autonomous body or private sector institutions, our rage should not be directed at these poor students to jeopardise their carrier.

On behalf of all the hon. Members, I request the Government to initiate legislative process so that we can at least stand by these students and let them appear for this exam. In phases we can do away with it. But this has to be done for the entire country. It is not that I am speaking on behalf of West Bengal only, I am speaking on behalf of other States like Maharashtra, Tamil Nadu, Telangana, etc., where students are preparing for the State exams.

Madam Speaker, we need doctors. Usually, in remote areas, the doctors are lacking. I have pleasure to inform that in the State of West Bengal we have established 34 multi-speciality hospitals and we need a lot of doctors there. For many years the seats have not been filled up. When the students are preparing at their own to appear for the exam, they have been disallowed to sit in the exam. In my power I beseech upon you that Health being a Concurrent Subject, let us stand by these students, the young Indians. We are their elders; we are like their parents; we are their guide and we cannot let them suffer. We have to stand by these students.

Maybe, a decision has been taken to phase out the State exam, it can be done over a period of time. But, now the exam is in July. This exam takes almost two to three years for preparation. How can these students sit for a separate exam of the Central Board in a different language when they are studying in regional languages? The Constitution gives respect to all languages. We cannot suddenly ask them to take the exam in a different language. So, we have to stand by them and allow them to appear in the exam being held by the State. Thank you.

HON. SPEAKER: S/ Shri

P.P. Chaudhary,

Sankar Prasad Datta,

Aparupa Poddar,

Kavitha Kalvakuntla and

Dr. Kirit P. Solanki are permitted to associate with the issue raised by Dr. Kakoli Ghosh Dastidar.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : मैडम स्पीकर, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विÂषय पर बोलना चाहता हूं। आज केन्द्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नेशनल इलिजिब्लिटी इंट्रेंस टेस्ट के लिए सात रिजनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम देने को कहा गया है। उसका मैं स्वागत करता हूं। मगर, मुझे इस बात का दुःख है कि उन सात रिजनल लैंग्वेज के साथ जो पंजाबी लैंग्वेज है, उसे इसमें नहीं लिया गया। पंजाबी लैंग्वेज, जो आज देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों में पढ़ी-लिखी जाती है और कम से कम हमारे देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा, जहां पंजाबी नहीं रहते। पंजाब के अलावा हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ में पंजाबी लैंग्वेज सेकेन्ड लैंग्वेज मानी जाती है। फिर इस एग्ज़ाम में पंजाबी भाÂषा को क्यों नहीं लिया गया?

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां सात रिजनल लैंग्वेजेज ली गयी हैं, वहां पंजाबी भाष्Â○ा को भी इसमें जोड़ा जाए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस हाउस में हमें इस बात का जरूर विश्वास दिलाया जाए। यह विÂषय बहुत ही महत्वपूर्ण विÂषय है और भावनात्मक विÂषय है। ये लोग तो हमारे साथ 60-65 सालों से न्याय करते रहे। आज की सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि हमें इंसाफ दिया जाए।

HON. SPEAKER:

Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Prem Singh Chandumajra.

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : माननीय अध्यक्ष जी, मेडिकल इंट्रेंस के संदर्भ में जो ईश्यू है, पिछले दस दिन से हम बात कर रहे हैं, मुझे इस पर बात करने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है मेडिकल इंट्रेंस परीक्षा के संदर्भ में, इससे छात्रों में संदिग्धता हर दिन बढ़ती जा रही है। पर्टिकुलरली महाराष्Âट्र में, महाराÂष्ट्र सरकार ने हर बार कहा था कि हम स्टेट इंट्रेंस के द्वारा ही एडमिशन करेंगे, इसमें छात्रों को डरने की कोई बात नहीं है। इसके बावजूद जो सर्वोच्च न्यायालय का कल निर्णय था, इससे महाराÂष्ट्र के 80 प्रतिशत छात्रों को इफेक्ट होगा। पिछले हफ्ते सदन में सरकार ने जो बात रखी थी, सदन में यह कहा था कि इसमें केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैं उसे कोट करना चाहूंगा।

> "It has been submitted by the learned counsel appearing for all the respondents that it is proposed to hold the examination in pursuance of notification dated 21st December, 2010."

रेस्पोंडेंट कौन है, रेस्पोंडेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद सीबीएसई और एमसीआई। इसका मतलब यह है कि केन्द्र सरकार कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में अपनी भूमिका रखने में कम रही है। मेरा सरकार से आग्रह है, जो हुआ छोड़ दीजिए, लेकिन इसके आगे कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, इसके बारे में एक तो सुप्रीम कोर्ट आप वापस जाइए, अदरवाइज आर्डिनेंस लेकर आइए, क्योंकि यह देश के सभी छात्रों के संबंध का विÂषय है।

माननीय अध्यक्ष :

कुमारी सुÂिष्मता देव को श्री राजीव सातव द्वारा उठाए गए विष्Â○ाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सब लोग एक-एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें। यहां से भी बहुत से लोग बोलने वाले हैं।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : अध्यक्ष जी, सब इस बात को जानते हैं कि जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उस उम्र के बच्चों के लिए, सबके घर में यह होता है, वह बड़ी परेशानी का सबब रहता है। इसकी तैयारी दो साल, तीन साल पहले से शुरू करते हैं। लेकिन जब एग्जाम होने वाला है तो सरकार, चाहे केन्द्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे एजेंसीज हों जो इसको कंट्रोल करती हैं, उनकी दो साल, तीन साल एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए। जब एकदम इम्तिहान के दरवाजे पर हैं बच्चे, उस वक्त यह फैसला आता है, तो तैयारी में उनकी मानसिक स्थिति क्या बनती है?

दूसरी बात, जो वर्नाकुलर है, हम स्टैंडर्डाइज हों, पारदर्शी हों, ट्रांसपेरेंट हों, लेकिन इसके साथ-साथ जो 50-60 लाख रुपए में सीट्स बिकती हैं, उसका भी अंत होना चाहिए। मेरिट के आधार पर जब यह होगा, तो आपको यूनिफार्म लेवल प्लेइंग ग्राउंड देना पड़ेगा। जो अलग-अलग जुबान के बच्चे हैं, रीजनल लैंगुएज के, वे इसमें नहीं हो सकते हैं। अलग-अलग बोर्ड का अलग-अलग सिलेबस है। आईसीएसई, सीबीएसई, बंगाल बोर्ड या बिहार बोर्ड सब अलग-अलग मामले हैं। मैं समझता हूं कि संसद इस मामले में, सरकार जब फैसला नहीं कर पाती है तब सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल **करना** पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं है।

श्री मोहम्मद सलीम : सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला हो रहा है, वह हमें यहां भविÂष्य के बारे में करना चाहिए था। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने भी उठाया है, मैं पहले भी सबको मौका दे चुकी हूं।

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam, I want to draw your attention.

When hon. Shri Altamas Kabir was the Chief Justice of India, at that time, there was a 2:1 division in the bench and it was decided that regional languages would be permitted and examination would be held in regional languages. The same court, now probably because of a weak case put up by the Federal Government, has done a flip-flop. This time they are talking about a national level joint entrance examination.

What is happening is that in regions where the local languages are important, the students are preparing in that language and this kind of a confusion means that as administrators, we are playing with the lives of innocent children. Now, doctors are badly required in this country. There is no second opinion about that. So, I think, the Union Government, the Federal Government should come out with a clear stand and go back to the court, as other hon. Members have suggested. We, from the Biju Janata Dal, also have this request.

What is happening now is that students from the North-East are getting admitted to the SCB Medical College in Cuttack. Similarly, students from Kashmir, they are going to Tamil Nadu. There is an hon. Minister also who is an example. There are so many cases like that. It is important that the Government takes a clear stand and clarifies this matter. We should stop playing with the lives of innocent students. Otherwise, we will be doing a lot of damage to the future generation.

Thank you.

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : अध्यक्ष जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि छात्रों को क्षेत्रीय भाÂषाओं में परीक्षा देने का अवसर मिलना चाहिए ताकि छात्रों का अहित न हो, लेकिन एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि इस से पहले जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस छात्रों को लूट रहे थे, 80-80 लाख रुपये ले कर एडमिशन कर रहे थे, कम से कम वह बुराई दूर हुई है, मैं स्वागत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री हुकुम सिंह द्वारा उठाए गए विष्Âाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : अध्यक्ष महोदया, डॉ. काकोली जी ने एक महत्वपूर्ण विÂषय सदन के सामने रखा है, मिस्टर सावंत ने इस विष्Âाय के बारे में कहा है, पहले भी कुछ मात्रा में सदन के सामने यह विष्Âाय आया, उस समय मैंने कहा कि मैं आप लोगों की भावना को हेल्थ मिनिस्टर को कन्वे कर दूंगा और मैंने उसी दिन कन्वे कर दिया। मगर विष्Âाय यह है कि इस में दो व्यूज़ हैं, एक जनरल कॉमन इंट्रेंस इन्जामिनैशन होना चाहिए, कारण क्या है, प्राइवेट वाले अपना इन्जाम कर रहे हैं, स्टेट अपना कर रहे हैं और कुछ राज्यों में और कुछ हो रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, यह भी कुछ लोगों का कहना है।

The Government, in general and in principle, is broadly in favour of a Common Entrance Examination. But at the same time, this is not the decision of the Government. This is the directive of the court. I do agree with the Members from all sides and even I have my own personal experience that you cannot expect children all of a sudden to switch over to a new system without getting prepared for the same. This is one aspect.

Secondly, children who are in CBSE are all studying in English medium whereas children in ISC and other courses are studying in regional languages. In the country, to my knowledge, only 18 per cent of students are studying in English medium and all others are studying in their mother tongue only. So, this being the case, this has to be appreciated by the court.

I will definitely convey it once again -- because I am not directly dealing with that matter -- to the HRD Minister, the Health Minister and also the Personnel Minister who is very much here to see that the Central Government has already taken up this issue. We are for a Common Entrance Examination, but not from this year. You give time and let the students prepare adequately and then go for the examination. This is the stand of the Central Government. We will reiterate the stand and we will try to convince the Supreme Court. ...(*Interruptions*)

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Sir, your stand is not clear. ...(*Interruptions*) You are not able to convey it effectively. ...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : If my advocate is weak, then I have to hire Shri Tathagata with no fees because he is saying that our stand is good, but we are not able to put it across effectively.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐट लिस्ट इस साल के लिए डेफर कीजिए, एक साल के लिए डेफर कीजिए। Naturally, all students will know that in the next year we have to face the Common Entrance Test. इसीलिए वह महत्वपूर्ण है, अगर वह कन्वे कर दिए तो सभी जगह थोड़ी पीस हो जायेगी।...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : यह कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, यह बहुत गंभीर मामला है, देश भर में लाखों बच्चे विचलित हैं, they are all concerned. हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं।

I agree with him. This is what I was trying to submit to the House. We will convey to the hon. Court also, through our Attorney General or whoever is appearing, saying that children need some time.

Moreover, I would like to share with the House that some of the State Governments have also gone to the court. They are also putting forth their point of view. So, keeping all these things in mind, Madam Speaker, I will convey it. ...(*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, the Government of West Bengal has gone to the court. ...(*Interruptions*)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : पंजाबी भाÂषा का ध्यान रखिए। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: It is okay.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, he has given reply on the issue.

...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री शैलेश कुमार जी।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब यह विष्Âाय हो गया। मैंने आप सभी का नाम सपोर्ट करते हुए लिया है। रत्ना डे जी, आपने अपनी बात सदन में रख दी, मैंने आपका नाम ले लिया।